



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052025-263454
CG-DL-E-29052025-263454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392]
No. 392]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2025/ज्येष्ठ 8, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2025/JYAISTHA 8, 1947

यूको बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2025

सं. एचओ / ईएसटी/2025 – 26 / 25 - बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूको बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद और केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र संख्या 4/2/1/2022-IR, दिनांक 13 मार्च, 2024, 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक, यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

- (i) इन विनियमों को यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में (इसके बाद उक्त के रूप में संदर्भित) विनियम 3 में, -
खंड (च) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“ (च) चिकित्सा सुविधाओं और छुट्टी किराया रियायत के प्रयोजन के लिए "परिवार" से तात्पर्य है: -

- अधिकारी कर्मचारी का पति/पत्नी,
- पूर्णतः आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चे और विधिकपूर्वक गोद लिए गए बच्चे सहित)
- पूर्णतः आश्रित शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग भाई/बहन जो 40% या उससे अधिक

विकलांगता वाले हों,

(iv) विधवा पुत्रियाँ और आश्रित तलाकशुदा/अलग हुई पुत्रियाँ,

(v) अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त या पति से अलग हुई/विधवा बहनें,

(vi) माता-पिता जो कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों।

बशर्ते शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के मामले में, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, उन्हें विवाह के बाद भी आश्रित माना जाएगा, बशर्ते वे आश्रित के लिए आय संबंधी मानदंड को पूरा करते हों।

स्पष्टीकरण 1 - "पूर्णतः आश्रित पारिवारिक सदस्य" शब्द का तात्पर्य परिवार के ऐसे सदस्य से है जिसकी आय ₹18,000/- प्रति माह से अधिक नहीं है। यदि माता-पिता में से किसी एक की आय ₹18,000/- प्रति माह से अधिक है या माता-पिता दोनों की कुल आय ₹18,000/- प्रति माह से अधिक है तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना और छुट्टी किराया रियायत के प्रयोजन के लिए, सभी अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों के लिए आश्रित माता, पिता, सास या ससुर में से किन्हीं दो को कवर किया जाएगा। अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी के पास एक कैलेंडर वर्ष में एक बार आश्रितों में से किसी एक या दोनों को प्रतिस्थापित करने का विकल्प होगा।

स्पष्टीकरण 3- उपर्युक्त परिभाषा 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी। कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए, चिकित्सा बीमा योजना/पॉलिसी के प्रयोजन के लिए, आश्रितों की संशोधित मासिक आय मानदंड 1 नवंबर, 2024 से प्रभावी होगी।

3. उक्त विनियमनों के विनियम 4 में, -

(क) उप विनियम 7 में स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ;

(ख) उप-विनियम 8 और 9 के लिए निम्नानुसार उप - विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा : -

“(8) 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद से प्रत्येक श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे :-

(क) उच्च कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII = ₹156500 – 4340/4 – 173860

वेतनमान VI = ₹140500 – 4000/4 – 156500

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V = ₹120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 – 135020

वेतनमान IV = ₹102300 – 2980/4 – 114220 – 3360/2 – 120940

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III = ₹85920 – 2680/5 – 99320 – 2980/2 – 105280

वेतनमान II = ₹64820 – 2340/1 – 67160 – 2680/10 – 93960

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान I = ₹48480 – 2000/7 – 62480 – 2340/2 – 67160 – 2680/7 – 85920

स्पष्टीकरण - प्रत्येक अधिकारी जो 31 अक्टूबर, 2022 को लागू वेतनमान द्वारा शासित है, उन्हें 1 नवंबर 2022 को चरण-दर-चरण आधार पर इस उप-विनियमन में निर्धारित वेतनमान में फिट किया जाएगा, अर्थात् संबंधित वेतनमान में पहले चरण से आगे के अनुरूप चरणों में और वेतन वृद्धि हमेशा की तरह वार्षिक नियत तारीख को होगी, सिवाय जहां अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

(9) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए वेतनमान निम्नानुसार होगा :

शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VIII = Rs.253000 - 9000/4 - 289000

(10) उप-विनियम (1) से (9) में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि बैंक को इन सभी ग्रेडों में सेवारत अधिकारियों को हर समय आवश्यकता होती है।

(11) (क) 1 नवम्बर, 2012 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा:-

वेतनमान I – III - मूल वेतन का 7.75% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV – V - मूल वेतन का 10% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI – VII - मूल वेतन का 11% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

(11) (ख) 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा:-

वेतनमान I – III - मूल वेतन का 16.40% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV – V - मूल वेतन का 19% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI – VII - मूल वेतन का 20% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

(12) (क) 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा:-

वेतनमान I - मूल वेतन का 26.50% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान II-III - मूल वेतन का 28.30% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV – V - मूल वेतन का 30.50% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI – VII - मूल वेतन का 31.50% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

(12) (ख) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए विशेष भत्ता निम्नानुसार होगा :

विशेष भत्ता वेतनमान VIII = मूल वेतन का 28.30% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

नोट : - उप-विनियम 11(क), 11(ख), 12(क) और 12(ख) में संदर्भित विशेष भत्ते को उस पर लागू महंगाई भत्ते के साथ सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नहीं माना जाएगा, जैसे कि पेंशन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) सहित , भविष्य निधि और ग्रेच्युटी ।”

4. उक्त विनियमनों के विनियम 5 में, -

(क) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : -

“(1) विनियम 4 के उप-विनियम 8 के प्रावधानों के अधीन, 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से वेतन वृद्धि निम्नलिखित के अधीन दी जाएगी, यथा : -

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (8) एवं (9) में निर्धारित वेतनमान में निर्दिष्ट वेतन वृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के अधीन, वार्षिक आधार पर अर्जित होगी तथा जिस माह में यह देय होगी, उसके प्रथम दिन को प्रदान की जाएगी;

(ख) अपने-अपने वेतनमानों में अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष बाद, वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को, खंड (ग) और खंड (घ) में निर्दिष्ट अगले उच्चतर वेतनमान में गत्यरोध वेतनवृद्धि सहित आगे वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी, बशर्ते वे दक्षता बार को पार कर लें;

(ग) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I के अधिकारी, जो उच्चतर वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद खंड (ख) के अनुसार मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के वेतनमान में चले गए हैं, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के पश्चात सात गत्यरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहले दो वेतन वृद्धियां 2680/- रुपये और अगली पांच वेतनवृद्धियां 2980/- रुपये प्रत्येक की होंगी।

बशर्ते अधिकारी पांचवीं गत्यरोध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, छठी गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

आगे यह भी कि अधिकारी पांचवीं गत्यरोध वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, सातवीं गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे ;

(घ) मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के अधिकारी, जो खंड (ख) के अनुसार उच्चतर वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के वेतनमान में चले गए हैं, वे सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के पश्चात 2980/- रुपये की सात गत्यरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे :

बशर्ते अधिकारी पांचवीं गत्यरोध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, छठी गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

बशर्ते अधिकारी पांचवीं गत्यरोध वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, सातवीं गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे ;

(ङ) मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के अधिकारी अर्थात् वे जो मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में भर्ती किए गए हैं या पदोन्नत किए गए हैं, वे अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के बाद प्रत्येक दो वर्ष पूर्ण की गई सेवा के उपरांत आठ गत्यरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहले चार गत्यरोध वेतन वृद्धि 2980/- रुपये की होगी और अगली चार गत्यरोध वेतन वृद्धि 3360/- रुपये प्रत्येक की होगी:

बशर्ते अधिकारी छठी गत्यरोध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, सातवीं गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

बशर्ते अधिकारी छठी गत्यरोध वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात या 1 नवम्बर 2022, जो भी बाद में हो, आठवीं गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे ;

(च) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV के अधिकारी, वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के पश्चात, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के उपरांत पाँच गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहली गत्यरोध वेतनवृद्धि 3360/- रुपये की होगी और अगली चार गत्यरोध वेतनवृद्धि 3680/- रुपये प्रत्येक की होगी :

बशर्ते अधिकारी दूसरी गत्यरोध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, तीसरी गत्यरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे :

बशर्ते अधिकारी दूसरी गत्यरोध वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, चौथी गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

बशर्ते अधिकारी दूसरी गत्यरोध वेतनवृद्धि जारी होने के छह वर्ष पश्चात या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, पांचवीं गत्यरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे ;

(छ) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-V के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के पश्चात 4000/- रुपये प्रत्येक की चार गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

बशर्ते अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के चार वर्ष पश्चात् या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, द्वितीय गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

इसके अतिरिक्त, अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के छः वर्ष पश्चात् या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, तृतीय गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

इसके अतिरिक्त, अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के आठ वर्ष पश्चात् या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, चतुर्थ गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे ;

(ज) शीर्ष प्रबंधन श्रेणी वेतनमान VI के अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के पश्चात सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के पश्चात तीन गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहली दो गत्यरोध वेतनवृद्धि 4000/- रुपये प्रत्येक की होंगी और तीसरी गत्यरोध वेतनवृद्धि 4340/- रुपये की होगी :

बशर्ते जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, 4000/- रुपये की पहली गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

बशर्ते जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के चार वर्ष पश्चात या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, 4000/- रुपये की दूसरी गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

बशर्ते जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के छह वर्ष पश्चात या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, 4340/- रुपये की तीसरी गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे ;

(झ) शीर्ष प्रबंधन श्रेणी वेतनमान VII के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के पश्चात सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के पश्चात 4340/- रुपये प्रत्येक की तीन गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे ;

बशर्ते जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, प्रथम गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे ;

इसके अतिरिक्त, जो अधिकारी पहले ही वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के चार वर्ष पश्चात या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, द्वितीय गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

इसके अतिरिक्त, जो अधिकारी पहले ही वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के छह वर्ष पश्चात या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, तृतीय गत्यरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे;

नोट - इस विनियम के उप-विनियम (क) से (झ) में उल्लिखित वेतनवृद्धि/वृद्धियां उस अधिकारी को नहीं दी जाएंगी जो पदोन्नति किए जाने पर उसे अस्वीकार कर देते हैं।

स्पष्टीकरण - इस उप-विनियम के तहत अगले उच्चतर वेतनमान में इस तरह की वेतनवृद्धि प्रदान करना पदोन्नति नहीं

माना जाएगा और अधिकारियों के विशेषाधिकार, अनुलाभ, कर्तव्य और जिम्मेदारियां उनके मूल पदों के अनुसार जारी रहेंगी।” ;

(ख) उक्त विनियमों के उप-विनियम (2) में -

(i) स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाने चाहिए :-

“ बशर्ते 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद से भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट सीएआईआईबी या (सीएआईआईबी-II) परीक्षा के भाग II पूर्ण करने वाले अधिकारी जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन बैंकर्स परीक्षा (जेएआईआईबी) या प्रमाणित एसोसिएट ऑफ इंडियन बैंकर्स परीक्षा के भाग I (सीएआईआईबी-I) को पूर्ण करने के लिए एक वेतनवृद्धि के अलावा अपने वेतनमान में दो वेतनवृद्धि के पात्र होंगे :

बशर्ते जो अधिकारी 1 नवंबर, 2022 तक बैंक की सेवाओं में थे और पूर्व में ही जेएआईआईबी/सीएआईआईबी-II/सीएआईआईबी II पूरा कर चुके हैं, वे 1 नवंबर, 2022 या जेएआईआईबी/सीएआईआईबी-I/सीएआईआईबी II उत्तीर्ण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से द्वितीय अतिरिक्त वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते यह भी कि यदि किसी अधिकारी ने 8 मार्च, 2024 तक या वेतनमान के शीर्ष/अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद (जेएआईआईबी/सीएआईआईबी के मामले में) या वेतनमान के अधिकतम स्तर से एक स्तर कम स्तर पर पहुंचने के बाद (जेएआईआईबी/सीएआईआईबी II/सीएआईआईबी II के मामले में) जेएआईआईबी/सीएआईआईबी या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी II) प्राप्त कर लिया है या प्राप्त करेगा, और उसने ऐसी योग्यता प्राप्त करने के कारण अन्यथा प्राप्य वेतनवृद्धि अर्जित नहीं की है, जब उन कर्मचारियों के वेतनमान में कोई वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की गई थी, तो ऐसे मामलों में स्थिर वेतन वृद्धि एक वर्ष या दो वर्ष के लिए अग्रिम दी जा सकती है, जैसा भी मामला हो।”

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (ज) के पश्चात् और नोट से पूर्व, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-

“(i) 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद, अन्य विषय-वस्तु समान होने पर, व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता वेतन की प्रमाणा नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट अनुसार संशोधित होंगी :-

(1)	(2)
जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट (जेएआईआईबी) या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट पार्ट I (सीएआईआईबी-I) परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है	(i) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् 1370/- रुपये प्रति माह।
जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के दोनों भाग उत्तीर्ण कर ली है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी-II) के दोनों भाग उत्तीर्ण कर ली है	(i) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् 1370/- रुपये प्रतिमाह। (ii) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात् 3425/- रुपये प्रतिमाह; (iii) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के तीन वर्ष पश्चात् 5480/- रुपये प्रतिमाह;

बशर्ते वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद भारतीय बैंकर्स संस्थान के जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (दोनों में से कोई एक या दोनों भाग) शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले अधिकारी कर्मचारी को ऐसी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता वेतन की पहली किस्त प्रदान

की जाएगी और व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता वेतन की बाद की किस्तों को जारी करना व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता वेतन की पहली किस्त जारी करने की तारीख के संदर्भ में होगी।"

(iii) नोट में, खंड (v) के बाद निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा :-

"(vi) अधिकारी जो 1 नवंबर 2022 तक बैंक की सेवाओं में थे और पूर्व ही जेएआईआईबी/सीएआईआईबी (सीएआईआईबी II) पास कर चुके हैं और व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता वेतन-II प्राप्त कर रहे हैं, वे व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता वेतन-II जारी होने के एक वर्ष पश्चात या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता वेतन-III के लिए पात्र होंगे।

(vii) ऐसे अधिकारी जिन्होंने जेएआईआईबी (सीएआईआईबी-I) या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-II) पास कर चुके हैं और 1 नवंबर 2022 को या उससे पूर्व वेतनमान में अधिकतम स्तर पर पहुंच गए हैं और 1 नवंबर 2022 को या उससे पूर्व प्रथम गत्यरोध वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं की है, वे 1 नवंबर, 2022 से व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता वेतन-I के लिए पात्र होंगे और व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता वेतन की बाद की किस्त इस खंड के तहत व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता वेतन I जारी होने की तारीख के संदर्भ में जारी की जाएगी।

(viii) व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता, यदि लागू हो, तो वेतनमान VIII के लिए बंद कर दिया जाएगा और वेतन परची घटकों का हिस्सा नहीं होगा।"

(ग) उप-विनियम (3) में -

- (i) खंड (छ) के बाद का नोट हटा दिया जाएगा।
- (ii) खंड (छ) के बाद निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा :

(ज) अन्य बातें समान होने के कारण, शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान-VIII में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो, के साथ निश्चित वैयक्तिक वेतन नीचे दी गई तालिका में दी गई दरों पर देय होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेंगे :-

तालिका

वेतनवृद्धि घटक (रु.)	1 नवंबर, 2022 को वेतनवृद्धि घटकों पर महंगाई भत्ता (रु.)	जहां बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक वेतन (रु.)
(1)	(2)	(3)
9000	669	9669

"(झ) 1 नवंबर, 2022 को एवं उसके बाद से, अन्य विषय-वस्तु समान होने पर, मकान किराया भत्ते के साथ नियत वैयक्तिक वेतन निम्नलिखित दरों पर होगा और पूरी सेवा अवधि के लिए स्थिर रहेगा :-

तालिका

वेतनवृद्धि घटक (रु.)	1 नवंबर, 2022 को वेतनवृद्धि घटकों पर महंगाई भत्ता (रु.)	जहां बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक वेतन (रु.)
(1)	(2)	(3)
2680	200	2880
2980	222	3202

3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663

नोट - (क) इस उप-विनियम के खंड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) और (झ) में तालिका के कॉलम (3) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता/ नियत वैयक्तिक वेतन उन अधिकारियों को देय होगा, जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ख) मकान किराया भत्ते के पात्र अधिकारियों के लिए निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन, खंड (झ), (ज) के अंतर्गत उक्त तालिका के कॉलम (1) और (2) के तहत विनिर्दिष्ट कुल राशि होगी तथा संबंधित अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) और (9) में विनिर्दिष्ट प्रासंगिक वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि अर्जित करने पर प्राप्त मकान किराया भत्ता होगा;

(ग) केवल वे अधिकारी जो 1 नवंबर, 1993 को या उसके पूर्व से बैंक की सेवा में रहे हैं, वे अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के एक वर्ष पश्चात नियत वैयक्तिक वेतन के लिए पात्र होंगे।

(घ) 1 नवंबर, 1999 को और उसके बाद नियत वैयक्तिक वेतन जारी होने के कारण उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (ग) के अनुसार व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता वेतन जारी करने की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

बशर्ते जहां व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता वेतन की कोई किस्त, जो पूर्ववर्ती प्रावधानों के कारण एक वर्ष के लिए अग्रोषित कर दी गई है और 1 नवम्बर, 1999 को या उसके पश्चात जारी होने वाली है, वह अधिकारी को इसी तारीख से जारी की जाएगी और व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 1 नवम्बर, 2000 को जारी की जाएगी।

(ङ) नियत वैयक्तिक भत्ता या नियत वैयक्तिक वेतन का वेतनवृद्धि घटक सेवानिवृत्ति लाभों में गिना जाएगा।

(च) एक अधिकारी जिसने उपर्युक्त खंड (क) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि अर्जित की है, वह वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात, उपर्युक्त खंड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) एवं (झ) में उल्लिखित निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन की प्रमात्रा प्राप्त करेगा;

5. विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“7. नियत तिथि में वर्गीकरण - विनियम 6 के प्रावधानों के अधीन, नियत तारीख को बैंक में अधिकारियों के विभिन्न पदों को नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट अनुसार वर्गीकृत किए जाएंगे :-

तालिका

पद	श्रेणी या वेतनमान जिसमें है।
मुख्य महाप्रबंधक	शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान - VIII
महाप्रबंधक	शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान - VII
उप महाप्रबंधक	शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान - VI
सहायक महाप्रबंधक	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान - V
मुख्य प्रबंधक	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान - IV
वरिष्ठ प्रबंधक	मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान - III

प्रबंधक	मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान – II
सहायक प्रबंधक	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान – I

बशर्ते यदि उपर्युक्त वर्गीकरण से कोई कठिनाई या विसंगति उत्पन्न होती है, तो उसे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से मिलकर बनी समिति को या जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाए, निर्णय हेतु भेजा जाएगा।"

6. उक्त विनियमों के विनियम 21 में,-

(i) उप-विनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम (8) जोड़े जाएंगे, यथा :-

“(8) 1 नवंबर, 2022 को एवं उसके बाद से, -

(क) महंगाई भत्ता सूचकांक के प्रति प्रतिशत बिंदु पर वेतन का 1% देय होगा।

(ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 2016=100 के तिमाही औसत में 123.03 अंकों से अधिक की वृद्धि या कमी के प्रत्येक परिवर्तन के लिए उपर्युक्त तरीके से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। सीपीआई 2016 के प्रत्येक दूसरे दशमलव स्थान में 123.03 अंकों से अधिक के परिवर्तन के लिए वेतन पर महंगाई भत्ते में 0.01% परिवर्तन पर देय होगा।

(ग) महंगाई भत्ते की दर में परिवर्तन तिमाही आधार पर 1 मई, 1 अगस्त, 1 नवंबर और 1 फरवरी को निम्नलिखित आधार पर जारी किया जाएगा :-

महंगाई भत्ता जारी होने की तारीख	माह के सीपीआई अंक का तिमाही औसत	माह के लिए लागू
1 मई	जनवरी, फरवरी एवं मार्च	मई, जून एवं जुलाई
1 अगस्त	अप्रैल, मई एवं जून	अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर
1 नवंबर	जुलाई, अगस्त एवं सितंबर	नवंबर, दिसंबर एवं जनवरी
1 फरवरी	अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर	फरवरी, मार्च एवं अप्रैल

(घ) महंगाई भत्ते पर कोई सीमा नहीं होगी।

(ङ) तिमाही औसत निकालते समय केवल पहले दो दशमलव अंकों पर विचार किया जाएगा।

(ii) उक्त विनियमन के स्पष्टीकरण (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(ख) विनियमन 5 के उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण के अनुसार खंड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) और (झ) में निर्दिष्ट व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता वेतन महंगाई भत्ते के लिए गिना जाएगा” :

7. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा :-

“(1) 1 नवंबर, 2022 को एवं उसके बाद से,-

(क) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, वहां वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूल किए जाएंगे;

(ख) (ख) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, वह निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे, यथा :

तालिका	
कार्यस्थल	मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
1. ग्रुप ए में प्रमुख "ए" श्रेणी के शहर और समूह (क) के परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 10.0%
2. क्षेत्र I के अन्य स्थान और समूह ख के परियोजना क्षेत्र केंद्र तथा गोवा राज्य	वेतन का 9.0%
3. अन्य स्थान	वेतन का 8.0%

बशर्ते यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसे देय मकान किराया भत्ता वेतनमान के पहले चरण में वेतन के 0.35 प्रतिशत से अधिक आवास के लिए उसके द्वारा भुगतान किया गया वास्तविक किराया होगा जिसमें उसे उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150 प्रतिशत होगा।

नोट:- अधिकारियों के स्वामित्व वाले आवास की लागत से संबद्ध आवास किराया भत्ते के दावों को भी पहले की तरह आवास किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा।

8. उक्त विनियमों के विनियम 23 में,-

(क) उप - विनियम (1) और (2) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उप - विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(1) 1 नवंबर, 2022 को एवं उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम 1 में उल्लिखित स्थान पर सेवारत है, तो उस स्थान के लिए कॉलम 2 में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा।

तालिका	
स्थान	दर
(1)	(2)
1. क्षेत्र 1 एवं उससे ऊपर के स्थान तथा गोवा राज्य	रु. 2300/- प्रति माह
2. पांच लाख और उससे अधिक की आबादी वाले स्थान और राज्य की राजधानियां और चंडीगढ़, पुडुचेरी और पोर्ट ब्लेयर	रु. 1900/- प्रति माह

(2) 1 नवंबर, 2022 को एवं उसके बाद से विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

बशर्ते अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर उप-विनियम (10) के तहत प्रदान किए गए पहाड़ी और ईंधन भत्ते भी देय हैं, तो अधिकारी दोनों भत्तों में से केवल उच्चतर भत्ते को ही प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, दोनों नहीं।

(ख) उप विनियम (4), (5), (6) और (7) के लिए क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा : -

“(4) 1 अप्रैल, 2024 को एवं उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसके एक या एक से अधिक बच्चे पूर्व स्थान पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वह शैक्षणिक वर्ष के अंत तक, अधिकतम दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा 2500/- रुपये प्रति माह की दर से मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते यदि सभी बच्चे पूर्व स्थान पर पढ़ाई बंद कर दें तो ऐसा भत्ता देय नहीं रहेगा।

(5) 1 अप्रैल, 2024 को एवं उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह उस पद से जुड़ी परिलब्धियां प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिसमें वह प्रतिनियुक्त किया गया है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त, वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त कर सकता है, जो अधिकतम 7500/- प्रति माह तक हो सकता है और ऐसे अन्य भत्ते जो उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में पदस्थापना के समय लागू होते थे :

बशर्ते जहां उसे ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो उसी स्थान पर स्थित है या ऐसे प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में जो बैंक के स्वामित्व में नहीं है जहां वह प्रतिनियुक्ति से पूर्व पदस्थापित थे या ऐसे प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में जो बैंक के स्वामित्व में नहीं है, वहां उसे अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा जो अधिकतम 3750/- रुपये प्रति माह होगा:

बशर्ते जहां किसी अधिकारी को उसी नगरपालिका सीमा/शहरी समूह के भीतर किसी अन्य कार्यालय/शाखा में प्रतिनियुक्त किया जाता है, मेट्रो/प्रमुख ए श्रेणी के शहरों में जहां ऐसी प्रतिनियुक्ति की दूरी मूल शाखा/कार्यालय से 20 किलोमीटर और उससे अधिक है, वह विनियम 41 के उप-विनियम (4) में उल्लिखित विराम भत्ते के लिए पात्र होंगे।

(6) 1 अप्रैल, 2024 को एवं उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को उच्चतर वेतनमान के किसी पद पर एक बार में कम से कम चार दिन या एक कैलेंडर माह में कुल मिलाकर चार दिन की निरंतर अवधि के लिए स्थानापन्न होना अपेक्षित है, तो उसे अपने मूल वेतन के 15 प्रतिशत के बराबर स्थानापन्न भत्ता मिलेगा, जो उस अवधि के लिए आनुपातिक होगा जिसके लिए वह स्थानापन्न कार्य करता है और स्थानापन्न भत्ता केवल भविष्य निधि और पेंशन के प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में माना जाएगा।

बशर्ते जहां कोई अधिकारी विनियम 6 के तहत पदों के वर्गीकरण की समीक्षा के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है, तो वह वर्गीकरण की समीक्षा प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) 1 अप्रैल, 2024 को एवं उसके बाद से अधिकारी प्रत्येक लेखाबंदी के लिए प्रति तिमाही 1500/- रुपये के लेखाबंदी भत्ते के लिए पात्र होगा।” :

(ग) उप-विनियम (10), (11), (12) एवं (13) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा : -

“(10) 1 नवंबर, 2022 को एवं उसके बाद से एक अधिकारी नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट पहाड़ी और ईंधन भत्ते के लिए पात्र होगा, यथा : -

तालिका

स्थान (1)	दर (2)
(i) 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाला स्थान लेकिन 1500 मीटर से कम और मरकारा टाउन	वेतन का 2 प्रतिशत अधिकतम रु.1450/- प्रति माह
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक लेकिन 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2.5 प्रतिशत अधिकतम रु.1900/- प्रति माह
(iii) 3000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5 प्रतिशत अधिकतम रु.3750/- प्रति माह

नोट :

(क) 750 मीटर से अनधिक की ऊंचाई वाले स्थानों और जो उच्च ऊंचाई वाली पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, जिन तक 1000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई को पार किए बिना नहीं पहुंचा जा सकता है वैसे स्थानों पर पदस्थापित अधिकारियों को उसी दर पर पहाड़ी और ईंधन भत्ते का भुगतान किया जाएगा जितना 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले केंद्रों के लिए देय है।

ख) हिल और ईंधन भत्ता वर्तमान में ऐसे किसी भी केंद्र पर भुगतान किया जाता है जो उपरोक्त वर्गीकरण द्वारा कवर नहीं किया गया है उसे वापस ले लिया जाएगा। केवल ऐसा कोई अधिकारी जो 1 मई, 1989 से पहले ऐसे केंद्र पर पदस्थापित था और उस तारीख के बाद भी केंद्र पर पदस्थापित रहता है तो भत्ते की मात्रा जो वह 30 अप्रैल, 1989 को प्राप्त कर रहा था, उसे संरक्षित किया जाएगा और हर महीने भुगतान किया जाएगा जब तक वह उसी वेतनमान में उस केंद्र पर पदस्थापित रहता है।

(11) 1 नवंबर, 2022 को एवं उसके बाद से, एक अधिकारी महंगाई भत्ते सहित 850/- रुपये प्रति माह के अधिगम भत्ते के लिए पात्र होंगे।

नोट - लागू महंगाई भत्ते के साथ अधिगम भत्ते की गणना सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नहीं की जाएगी अर्थात् पेंशन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, नई पेंशन योजना, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी सहित।

(12) 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से, अधिकारी प्रति माह 1200/- रुपये के निश्चित स्थान भत्ते के लिए पात्र होगा, जो नगर प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में पदस्थापित हैं, उसकी गणना महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ यानी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना,, नई पेंशन योजना, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी सहित पेंशन के भुगतान के लिए नहीं की जाएगी।

(13) (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 से सभी अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों को बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार निम्नलिखित चयनित मापदंडों के मैट्रिक्स के आधार पर कार्य निष्पादन आधारित अनुलाभ देय होगा :

(i) चालू खाता बचत खाता (ii) अनर्जक आस्ति (iii) विशेष उल्लेख खाते (iv) गैर-व्याज आय (v) कुल कारोबार (vi) लाभप्रदता (vii) आस्ति पर प्रतिलाभ या इक्विटी पर प्रतिलाभ (viii) सरकारी योजनाएँ।

(13) (ख) प्रदर्शन लिंकड प्रोत्साहन राशि 0-15 (अधिकतम) दिवसों के वेतन (मूल+महंगाई भत्ता) के रूप में देय होगी, जो ऊपर खंड (क) में उल्लिखित मानदंड के मैट्रिक्स पर निर्भर करेगा जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा बैंक की प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

9. उक्त विनियमनों के विनियम 24 में,

उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा :-

“(1) 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से, कोई भी अधिकारी स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते अधिकारी ने स्वयं ऐसा व्यय करने का प्रमाण पत्र दिया हो, जो नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट दावा की गई राशियों के लिए लेखा विवरण द्वारा समर्थित हो, अर्थात्:-

तालिका	
श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु.13,000/- प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो।
वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक श्रेणी	रु.15,400/- प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो।

नोट - (1) किसी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमति दी जा सकेगी, जो किसी भी समय ऊपर दी गई अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक न हो;

नोट - (2) कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने यानी नवंबर, 2022 और दिसंबर, 2022 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।”

(ख) उप-विनियम (3) के बाद निम्नलिखित उप - विनियम जोड़े जाएंगे :

“(4) सभी अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी नेत्र जांच के लिए प्रति वर्ष 500 रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगे।

10. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(2) उप-विनियम (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, 1 नवंबर, 2022 को एवं उसके बाद से बैंक किसी अधिकारी को वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, का भुगतान अधिकारी द्वारा किए जाने पर आवासीय आवास उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होगा -

बशर्ते जहां अधिकारी को ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है, वहां वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.075 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि बैंक द्वारा उससे वसूली जाएगी -

आगे यह भी कि जहां ऐसी आवासीय सुविधा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, वहां बिजली, पानी, गैस और सफाई के व्यय का वहन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।”

11. उक्त विनियम के विनियम 31 में, निम्नलिखित प्रावधान जोड़े जाएंगे, यथा -

“बशर्ते जहां संस्वीकृति प्राधिकारी, अधिकारी को छुट्टी देने से इनकार करता है या उसको स्थगित करता है, तो वह इसके लिए कारणों को दर्ज करेगा।”

12. उक्त विनियमों के विनियम 32 में, उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित उप - विनियम जोड़े जाएंगे, यथा :

“(3) 1 अप्रैल, 2024 को एवं उसके बाद से, एक अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी एक वर्ष में चार अवसरों पर आधे दिन के लिए दो दिन की आकस्मिक अवकाश लेने के पात्र होंगे, जिसमें से दो अवसर सुबह और दो अवसर दोपहर में होंगे।

बशर्ते इस श्रेणी के तहत आकस्मिक अवकाश चौबीस घंटे पहले आवेदन करने के बाद लिया जाएगा।

बशर्ते आकस्मिक अवकाश के शेष को, उपयोग न किए गए आकस्मिक अवकाश खाते में ले जाने के समय, शेष अंश, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

13. उक्त विनियमनों के विनियम 33 में –

(क) उप-विनियम (4) एवं (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-

“(4) 1 जून, 2015 को या उसके बाद से साधिकार अवकाश अधिकतम 270 दिनों से अधिक जमा नहीं की जा सकती है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां अवकाश के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो।

बशर्ते 1 अप्रैल, 2024 से साधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम 255 दिनों तक सीमित रहेगा।

बशर्ते कोई अधिकारी अपनी पसंद के किसी भी त्यौहार के समय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 5 दिनों की दर से साधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए भी पात्र होंगे और कोई अधिकारी जो पूर्व ही 55 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुके हैं, वह अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 7 दिनों की दर से साधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्र होंगे।

“(5) साधिकार अवकाश लेने के इच्छुक अधिकारी को सामान्यतः अवकाश किराया रियायत के प्रयोजन को छोड़कर, ऐसे अवकाश लेने के कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना देनी होगी।

बशर्ते 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के सदस्यों के लिए साधिकार अवकाश का लाभ लेने के लिए 10 दिनों की ऐसी कोई अग्रिम सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) उप-विनियम (6) के बाद निम्नलिखित उप - विनियम जोड़े जाएंगे , यथा -

“(7) 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से साधिकार अवकाश की गणना के प्रयोजनों के लिए आकस्मिक अवकाश और अनिवार्य अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार के अवकाश को अपवर्जित किया जाएगा।”

14. उक्त विनियमनों के विनियम 34 में,-

(क) उक्त विनियम के उप-विनियम (1) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगे -

“बशर्ते 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से कोई भी अधिकारी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह की दर से बीमारी अवकाश के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते अधिकारी की संपूर्ण सेवा के दौरान बीमारी अवकाश की कुल संख्या (विनियम 35 में उल्लिखित अतिरिक्त बीमारी अवकाश सहित) सात सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगी।”

(ख) उप-विनियम (5) के बाद निम्नलिखित उप - विनियम जोड़े जाएंगे, यथा :-

“(6) 1 अप्रैल, 2024 को एवं उसके बाद से एकल पुरुष अभिभावक कर्मचारी अपने 8 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन बीमारी अवकाश का लाभ उठा सकते हैं।

(7) 1 अप्रैल, 2024 को एवं उसके बाद से कोई भी महिला कर्मचारी बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए प्रति माह एक दिन की बीमारी अवकाश ले सकेगी।

(8) 1 अप्रैल, 2024 को एवं उसके बाद से, अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी अपने 15 वर्ष या उससे कम आयु के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की बीमारी के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दस दिनों की अवधि के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन बीमारी अवकाश ले सकते हैं।

(9) 1 अप्रैल, 2024 को एवं उसके बाद से अट्वावन वर्ष या उससे अधिक आयु के अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीस दिनों की अवधि के लिए कार्यस्थल के अलावा किसी अन्य केंद्र पर अपने पति/पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने के लिए बीमारी अवकाश ले सकते हैं।

15. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, -

(क) उप-विनियम (1) (क) को निम्नलिखित उप - विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : -

“(1) (क) कोई महिला कर्मचारी अपने पूरे सेवा अवधि के दौरान किसी एक अवसर पर अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए तथा अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 12 माह के लिए मूल वेतन पर मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी।

बशर्ते जुड़वा बच्चों के जन्म के मामले में मातृत्व अवकाश की अवधि 8 माह होगी।

बशर्ते 1 अप्रैल 2024 को एवं उसके बाद से एक प्रसव में दो से अधिक बच्चों के जन्म की स्थिति में मातृत्व अवकाश की अवधि 12 माह होगी।

बशर्ते मातृत्व अवकाश का लाभ आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकता है।

(ख) उप-विनियम 1(घ) को निम्नलिखित उप-विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(1) (घ) एक महिला कर्मचारी एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए सेवा अवधि के दौरान एक बार में अधिकतम नौ माह की अवधि के लिए निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन छुट्टी ले सकती है: -

(क) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए छुट्टी दी जाएगी।

(ख) बच्चे को गोद लेना उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए और कर्मचारी को ऐसी छुट्टी की स्वीकृति हेतु बैंक में गोद लेने का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

(ग) ऐसे मामलों में जहां बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ है, जैविक मां को भी छुट्टी मिलेगी।

(घ) छुट्टी का लाभ सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह माह की समग्र पात्रता के भीतर लिया जाएगा।

(ग) उप-विनियम 1(ड) के बाद निम्नलिखित उप - विनियम जोड़े जाएंगे, यथा :

“1(च) 1 अप्रैल, 2024 को एवं उसके बाद से बारह माह की समग्र सीमा के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन इन विट्रो फर्टिलिटी (आईवीएफ) उपचार हेतु मातृत्व अवकाश का लाभ लिया जा सकता है।

1(छ) 1 अप्रैल, 2024 को एवं उसके बाद से, शिशु के मृत जन्म या जन्म के अट्ठाईस दिनों के भीतर शिशु की मृत्यु होने की स्थिति में महिला कर्मचारी द्वारा साठ दिनों तक विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ लिया जा सकता है।”

16. उक्त विनियम के विनियम 37क को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा :-

"37क. विशेष आकस्मिक अवकाश और विशेष छुट्टियां - (1) 1 नवंबर, 2020 से, कोई अधिकारी कर्मचारी उन अवसरों पर विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा जब वह शाखा जहां अधिकारी काम कर रहा है या वह स्थान जहां वह रह रहा है, काफ़ूरू, दंगों, निषेधात्मक आदेशों, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ आदि से प्रभावित होता है,

(2) 1 नवंबर, 2020 से, शारीरिक/अस्थि रूप से विकलांग अधिकारी चार दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश के पात्र होंगे।

(3) 1 अप्रैल, 2024 से अखिल भारतीय अधिकारी संघों/एसोसिएशनों के प्रमुख पदाधिकारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 25 दिनों तक का विशेष अवकाश प्रदान किया जाएगा।

(4) 1 अप्रैल, 2024 से, विभागीय जांच में शामिल रक्षा प्रतिनिधि अधिकारी, अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी का बचाव प्रस्तुतीकरण तैयार करने के उद्देश्य से एक दिन का विशेष अवकाश ले सकते हैं।

बशर्ते ऐसी विशेष अवकाश एक वर्ष में अधिकतम दस अवसरों पर ली जा सकेगी।

(5) किसी अधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश तथा केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा निर्णीत कोई विशेष अवकाश भी प्रदान किया जा सकता है।"

17. उक्त विनियमों के विनियम 37क के बाद निम्नलिखित विनियम को निम्नानुसार जोड़े जाएंगे, यथा :-

“ 37ख. शोक अवकाश - अधिकारी संवर्ग के किसी कर्मचारी को उसके परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी, बच्चों, माता-पिता और सास-ससुर) की मृत्यु होने पर उतने दिनों के लिए शोक अवकाश प्रदान किया जाएगा, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा तय किए जाने के अधीन होगा।

बशर्ते बीच की छुट्टियां शोक अवकाश का हिस्सा होंगी।

बशर्ते उक्त अवकाश का लाभ निधन के अधिकतम पंद्रह दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए।

बशर्ते उक्त अवकाश को साधिकार अवकाश की गणना के प्रयोजन हेतु 'सक्रिय सेवा' के रूप में नहीं माना जाएगा।

18. उक्त विनियमों के विनियम 41 में:-

क. उक्त विनियमों के उपविनियम (1) के लिए निम्नानुसार खंड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

-

“(1) 1 अप्रैल, 2024 को एवं उसके बाद से, जहां कहीं भी किसी अधिकारी को झूटी पर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थातः

(क) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी के अधिकारी राजधानी/शताब्दी/तेजस/वंदे भारत/अमृत भारत आदि जैसी प्रीमियम ट्रेनों (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर) सहित किसी भी ट्रेन में एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने हेतु पात्र होंगे।

बशर्ते वह हवाई जहाज से (इकोनॉमी क्लास में) यात्रा कर सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय या सार्वजनिक हित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनुमति दी गई हो।

(ख) मध्य प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी उपर्युक्त खंड (क) में उल्लिखित प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन में एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के पात्र होंगे।

बशर्ते यात्रा की जाने वाली दूरी पाँच सौ किलोमीटर से अधिक है तो वह हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकते हैं;

बशर्ते वह हवाई जहाज से (इकोनॉमी क्लास में) कम दूरी के लिए भी यात्रा कर सकते हैं, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय या सार्वजनिक हित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनुमति दी गई हो;

(ग) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी प्रीमियम ट्रेनों (जैसा कि ऊपर खंड क में उल्लिखित है) या हवाई (इकोनॉमी क्लास) सहित किसी भी ट्रेन में एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के पात्र हैं;

(घ) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी हवाई या रेल सेवा उपलब्ध न होने वाले स्थानों के बीच कार से यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते कि दूरी पाँच सौ किलोमीटर से अधिक न हो;

बशर्ते जब दो स्थानों के बीच की दूरी का बड़ा हिस्सा हवाई जहाज या रेल द्वारा तय किया जा सकता हो तो शेष दूरी सामान्यतः कार द्वारा तय की जानी चाहिए;

(ङ) किसी अन्य अधिकारी को व्यवसाय की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने स्वयं के वाहन या टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है;

(च) किसी भी श्रेणी या वेतनमान का अधिकारी सड़क या हवाई या रेल सेवा उपलब्ध न होने वाले स्थानों के बीच डीलक्स केबिन श्रेणी में जल परिवहन द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र होंगे।

(छ) एक अधिकारी प्रीमियम ट्रेनों (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर) के किराये के लिए पात्र होंगे;

नोट 1- ट्रेन किराए पर लगाए गए जीएसटी प्रभार पात्रता से अलग होगा।

नोट 2. प्रचलित मांग (डायनेमिक) किराया प्रणाली के मद्देनजर, बुकिंग की तिथि पर प्रयोज्य रेल टिकटों की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ख) उप-विनियम 4 में खंड (क) एवं (ख) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा :-

“ 4 (क) 1 अप्रैल, 2024 को एवं उसके बाद से, तालिका के कॉलम (1) में दिए गए श्रेणी या वेतनमान में कोई अधिकारी कॉलम (2) में दी गई तदनु रूप दरों पर 'प्रतिदिन' विराम भत्ते का पात्र होगा, यथा :-

तालिका

अधिकारियों की श्रेणी/ वेतनमान	विराम भत्ता			
	मेट्रो रु.	प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर रु.	क्षेत्र I रु.	अन्य स्थान रु.
(1)	(2)			
वेतनमान VI एवं उससे ऊपर के अधिकारी	4050	2925	2475	2150
वेतनमान IV एवं V के अधिकारी	3375	2925	2475	2150
वेतनमान I, II एवं III के अधिकारी	2925	2475	2150	1800

बशर्ते जहां विराम की कुल अवधि आठ घंटे से कम लेकिन चार घंटे से अधिक हो, तो उपर्युक्त दरों की आधी दर पर विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण- विराम भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए "प्रतिदिन" का अर्थ चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि अथवा उसका पश्चावर्ती भाग होगा, जिसकी गणना हवाई यात्रा की दशा में प्रस्थान हेतु रिपोर्टिंग समय से तथा अन्य दशाओं में प्रस्थान के अभिप्रेत अनुसूचित निर्धारित समय से आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी और जहां विराम की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, वहां "प्रतिदिन" का अर्थ आठ घंटे की अवधि अभिप्रेत होगी।

4(ख) नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में निर्धारित ग्रेड या पैमानों में एक अधिकारी को वास्तविक होटल के खर्चों की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, जो भारत में एकल कमरे के आवास शुल्क तक सीमित है। पर्यटन विकास निगम होटल संबंधित स्टार श्रेणी के कॉलम (2) में निर्धारित हैं, जो निम्नानुसार है:

तालिका

अधिकारियों की श्रेणी / वेतनमान	ठहरने की पात्रता
(1)	(2)
वेतनमान- VI, VII और VIII	4 * स्टार होटल
वेतनमान- IV और V	3 * स्टार होटल
वेतनमान- II और III	2 * स्टार होटल (गैर-वातानुकूलित)
वेतनमान- I	1* स्टार होटल (गैर-वातानुकूलित)

बशर्ते बोर्ड, केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपर विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक प्रतिपूर्ति की जाने वाली अतिरिक्त सीमा निर्दिष्ट कर सकता है।

19. उक्त विनियमों के विनियम 42 में :

(क) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः:-

“(3) 1 अप्रैल 2024 को और उसके बाद से, अधिकारी के स्थानांतरण पर पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि से संबंधित व्यय हेतु एकमुश्त राशि की प्राप्ति का पात्र होगा, जो कि निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट हैं: -

तालिका

श्रेणी/वेतनमान	राशि
वरिष्ठ प्रबंधन एवं उच्च कार्यपालक (वेतनमान IV एवं ऊपर के अधिकारी)	रु.500000/-
कनिष्ठ प्रबंधन एवं मध्य प्रबंधन (वेतनमान III तक के अधिकारी)	रु.400000/-

(ख) उप-विनियम (4) में, परंतुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा :-

“बशर्ते 1 अप्रैल, 2024 को एवं उसके बाद से, जहां बैंक द्वारा किसी अधिकारी को नई पदस्थापना के स्थान पर कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है और जहां ऐसे अधिकारी को कार्यभार संभालने की प्रक्रिया में अपने नियंत्रण से परे कारणों से अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ता है, तब सक्षम प्राधिकारी, नए स्थान पर ऐसे अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पात्रता के आधार पर या तो (क) आवास और भोजन व्यय या (ख) 15 दिनों की अवधि के लिए या जब तक उसे आवास उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है, जो भी पहले हो, विराम भत्ता देने पर विचार कर सकता है।”

20. उक्त विनियमों के विनियम 44 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा :-

“44 (1) चार वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान एक अधिकारी दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार अपने निवास स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत हेतु पात्र होंगे:

बशर्ते, वह दो वर्षों के एक ब्लॉक में अपने निवास स्थान तक और दो वर्षों के दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान पर सबसे लघुत्तम मार्ग से यात्रा कर सकता है।

(2) 1 अप्रैल, 2024 को एवं उसके बाद से, वैकल्पिक रूप से, कोई अधिकारी चार वर्ष के ब्लॉक या दो वर्ष के ब्लॉक के दौरान किसी भी समय एक विकल्प का उपयोग करके, यथास्थिति हो, अपनी छुट्टी यात्रा रियायत (निवास स्थान की यात्रा के अलावा) को अभ्यर्पण और नकदीकरण कर सकता है, जिस पर वह रेल द्वारा यात्रा की श्रेणी के लिए प्रयोज्य किराए के बराबर राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसके लिए वह कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II तथा मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के अधिकारियों के लिए 5,500 किलोमीटर (एक तरफ) की दूरी तक और वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए 6,500 किलोमीटर (एक तरफ) की दूरी तक ट्रेन द्वारा यात्रा की उस श्रेणी हेतु पात्र किराये के बराबर राशि प्राप्त करने के पात्र है:

बशर्ते कोई अधिकारी अपनी छुट्टी यात्रा रियायत को भुनाने का विकल्प चुनता है, तो वह उस ब्लॉक के दौरान जिसमें ऐसी नकदीकरण सुविधा का उपभोग करता है, अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए केवल एक बार दावा प्रस्तुत करेगा और छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा लेते समय साधिकार छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा भी छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा के नकदीकरण के समय उपलब्ध होगी।

(3) वह माध्यम और श्रेणी जिसके द्वारा कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त कर सकेगा, वह वही होगा जैसा कि अधिकारी सामान्यतः स्थानांतरण पर यात्रा करने का हकदार होता है तथा अन्य नियम और शर्तें जिनके अधीन कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त कर सकेगा, वे समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

बशर्ते 1 अप्रैल, 2024 से, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I का अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय न्यूनतम किराया वाले इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने हेतु पात्र होगा, इस मामले में वास्तविक किराया अथवा यात्रा की दूरी हेतु रेल द्वारा एसी प्रथम श्रेणी हेतु प्रयोज्य किराया, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी और यही नियम छुट्टी किराया राहत का लाभ उठाते समय मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III पर भी लागू होगा, जहां दूरी पाँच सौ किलोमीटर से कम है।

(4) प्रत्येक चार वर्ष में एक बार जब कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ लेता है, तो उसे एक बार में 30 दिनों तक का साधिकार अवकाश को अभ्यर्पित करने और नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है या उसे दो वर्षों के एक ब्लॉक में अपने गृह नगर और अन्य ब्लॉक में भारत में किसी स्थान की यात्रा करते समय प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम पंद्रह दिन या एक ब्लॉक में तीस दिन साधिकार अवकाश के नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है तथा छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजन हेतु उस माह के लिए देय सभी परिलब्धियां स्वीकार्य होंगी, जिसके दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाया गया है।

बशर्ते किसी अधिकारी को अपनी इच्छानुसार प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने के लिए एक दिन का अतिरिक्त साधिकार अवकाश नकदीकरण की अनुमति होगी, बशर्ते वह इस आशय का एक पत्र बैंक को दे तथा बैंक को कोष में राशि भेजने के लिए प्राधिकृत करे।

(5) जहां पति और पत्नी दोनों एक ही बैंक में कार्यरत हैं, वहां छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ स्वतंत्र रूप से लिया जा सकता है।

(6) पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत कार्मिकों हेतु, छुट्टी यात्रा रियायत गुवाहाटी से शुरू होगी और उनके कार्यस्थल से गुवाहाटी तक का विहित रेल किराया अतिरिक्त रूप से भुगतान किया जाएगा।

(7) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से चेन्नई/कोलकाता, लक्षद्वीप से कोच्चि, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर या किसी अन्य क्षेत्र में दूर-दराज के क्षेत्र की शाखाएं जो सीधे ट्रेन से जुड़ी नहीं हैं, इन क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों के लिए सामान्य पात्रता के अतिरिक्त छुट्टी यात्रा रियायत के तहत उन्हें निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन तक के व्यय की अतिरिक्त रूप से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(8) बेंचमार्क विकलांगता वाले अधिकारी के साथ यात्रा पर जाने वाले अनुरक्षक को छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी, यथा :-

क) प्रत्येक अवसर पर सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

ख) अधिकारी की शारीरिक अक्षमता की प्रकृति ऐसी है कि यात्रा के लिए अनुरक्षक की आवश्यकता होती है। संदेह की स्थिति में विभागाध्यक्ष/नियंत्रक का निर्णय अंतिम होगा।

ग) ऐसी बेंचमार्क विकलांगता वाले अधिकारी के पास उसके साथ आश्रित परिवार का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।

घ) ऐसे बेंचमार्क विकलांगता वाले अधिकारी और अनुरक्षक को रेल/बस किराये में रियायत, यदि कोई हो, का लाभ उठाना होगा, जैसा कि ऐसे मामलों में रेलवे/राज्य रोडवेज प्राधिकारियों द्वारा दिया गया हो।

ङ) कोई अन्य व्यक्ति जो आश्रित के रूप में छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार है, यात्रा पर ऐसी बेंचमार्क विकलांगता वाले अधिकारी के साथ नहीं जाते हैं।

(9) जहां किसी अधिकारी ने छुट्टी यात्रा रियायत/अग्रिम छुट्टी के लिए आवेदन किया है और टिकट भी बुक किया है और प्रबंधन द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत अस्वीकार कर दी गई है या स्थगित कर दी गई है, तो निरसन शुल्क की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी।

(10) जहां किसी अधिकारी ने निर्धारित समय के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत/छुट्टी के लिए आवेदन किया है और उसे मंजूरी दे दी गई है और जब ट्रेन टिकटों की अग्रिम बुकिंग संभव नहीं है, तो तत्काल/प्रीमियम तत्काल के तहत खरीदे गए टिकटों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

21. उक्त विनियमों की अनुसूची हेतु निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित होंगी, यथा :-

“अनुसूची

(विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें)

नवंबर, 2022 की पहली तारीख को या उसके बाद से निम्न तालिका में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार अधिकारी उस समय तक विशेष भत्ता पाने का पात्र होगा जब तक इसे पूर्णतः या अंशतः हटाया या संशोधित नहीं किया जाता, यथा :-

तालिका
विशेष क्षेत्र भत्ता

क्र. सं.	स्थान	भत्ते (रुपये में)	
		रु.48,481/- से कम वेतन	रु.48,481/- से अधिक वेतन
1.	मिजोरम		
	क) चंफाई जिला तथा लुंगलेई से 25 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले क्षेत्र	4100	5300
	लुंगलेई जिले का शहर		
	ख) लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण लुंगलेई जिला	4100	5300
	ग) संपूर्ण आइजोल जिला	2700	3400
2.	नागालैंड	4100	5300
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		
	क) उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार और नर्कोदम द्वीपसमूह	4100	5300
	ख) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	4100	5300
4.	सिक्किम	4100	5300
5.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	4100	5300
6.	असम	1000	1200
7.	मेघालय	1000	1200
8.	त्रिपुरा		
	क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण त्रिपुरा	2700	3400
9.	मणिपुर	2700	3400
10.	अरुणाचल प्रदेश		
	क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश	2700	3400
11क.	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर		
	1) कठुआ जिला: नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मछोदी	4100	5300
	2) उधमपुर जिला:		
	(क) डुडु बसंतगढ़, लैंडर भमाग इलाका, ठाकराकोट और नागोटे	4100	5300
	(ख) नीचे (ग) में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर माहौर तहसील के सभी क्षेत्र	4100	5300
	(ग) तहसील मोहरे में कंबन की ओर से गोयल तक का क्षेत्र और केयासी की ओर से अरनास तक का क्षेत्र	4100	5300

	3) डोडा जिला: कश्मीर तहसील में पैडर और नियाबत नौगाम का इलाका	4100	5300
	4) बारामूला जिला:		
	(क) संपूर्ण गुरेज-निराबत, तंगदार उप-मंडल और केरन इलाका	4100	5300
	(ख) माछिल	4100	5300
	5) पुंछ और राजौरी जिले: पुंछ और राजौरी दोनों जिले में पुंछ और राजौरी तथा सुंदरबनी शहरों और दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर	2700	3400
	6) क्षेत्र जो उपर्युक्त (1) से (5) में शामिल नहीं हैं, किंतु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) की सीमा से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर हैं अथवा उन स्थानों पर जो या ऐसे स्थान हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ता दिए जाने योग्य स्थान घोषित किए जाते हैं।	2700	3400
ख.	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख: लेह जिला: नोयामा और नोब्रे ज़ांस्कर जिले के अन्य सभी स्थान	4100	5300
12.	हिमाचल प्रदेश		
	1) चंबा जिला		
	पांगी तहसील, भरमौर तहसील की निम्नलिखित पंचायतें एवं गाँव: पंचायत: बड़गांव, बजोल, देवल कुगटी, नयागम और टुंडा गाँव: ग्राम पंचायत जगत के घाटू, ग्राम पंचायत चौहटा के कनारसी	4100	5300
	भरमौर तहसील, उपर्युक्त (क) में शामिल पंचायतों और गांवों को छोड़कर	4100	5300
	भारतीयत तहसील में झांडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी शहर (बानीखेत सहित)	2700	3400
	2) किन्नौर जिला		
	क) आसरंग, चिटकुल और हांगो कूनो/चरांग पंचायतें, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नाथपा और रूपी, पूह उप-मंडल की ग्राम पंचायतें शामिल हैं, ऊपर विनिर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर	4100	5300
	ख) उपर्युक्त (क) में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण जिला	4100	5300
	3) कुल्लू जिला		
	क) निरमंड तहसील के 15/20 क्षेत्र, जिसमें खारगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायतें शामिल हैं।	4100	5300

	ख) बाहरी सेराज (निरमंड तहसील में जकात-खाना और बुरों के गांवों को छोड़कर) और संपूर्ण जिला बाहरी सराज क्षेत्र और पंडराबिस के परगना को छोड़कर, किंतु इसमें निरमंड तहसील के जगत-खाना और बुराओ गांव शामिल हैं)	2700	3400
	4) लाहौल और स्पीति जिला: लाहौल और स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र	4100	5300
	5) शिमला जिला		
	क) रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा और चंडी-ब्रांडा पंचायतें शामिल हैं।	4100	5300
	(ख) डोडरा-कवार तहसील, रामपुर में दरकाली ग्राम पंचायत, काशापाठ तहसील और मुनीश, सराहन परगना की गोरी चैबीस	4100	5300
	(ग) (I) चोपाल तहसील (i) घोरी, पंजगांव, पाटखौ, नौबीस और सराहन परगना की तीन कोटी, (ii) ताकलेश क्षेत्र का देवठी ग्राम पंचायत, (iii) बाराबीस परगना (iv) रामपुर कस्बा और रामपुर तहसील के रामपुर परगना का घोरी नोग, (II) शिमला शहर और उसके उपनगर (ढल्ली, जाटोग, कसुम्पटी, मशोब्रा, तारादेवी और तुतू)	2700	3400
	(6) कांगड़ा जिला:		
	क) बड़ा भांगल और छोटा भांगल के क्षेत्र	4100	5300
	(I) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर और नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय जो धर्मशाला शहर में शामिल किए गए हैं : क) महिला आईटीआई, दारी, ख) मैकेनिकल वर्कशॉप, रामनगर, ग) बाल कल्याण और नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय, सकोह, घ) सीआरएसएफ कार्यालय, निचला सकोह, ङ) कांगड़ा दूध आपूर्ति योजना, डुगियार, च) एचआरटीसी वर्कशॉप, साधेर, छ) आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दारी, ज) वन निगम कार्यालय, शामनगर, झ) चाय फैक्ट्री, दारी, ञ) आईपीएच उप-मंडल, दारी, ट) बंदोबस्त कार्यालय, शामनगर, ठ) बिनवा परियोजना, शामनगर,	2700	3400

	<p>(II) पालमपुर शहर में स्थित एचपीकेवीवी परिसर तथा पालमपुर शहर की सीमा से बाहर स्थित पालमपुर शहर में शामिल निम्नलिखित कार्यालय :-</p> <p>(क) हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परिसर,</p> <p>(ख) मवेशी विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बानूरी</p> <p>(ग) रेशम उत्पादन कार्यालय/इंडो-जर्मन कृषि कर्मशाला/एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुंदला</p> <p>(घ) विद्युत अनुमंडल, लोहना</p> <p>(ङ) डीपीओ निगम, बुंदला</p> <p>(च) विद्युत एचपीएसई मंडल, घुग्गर</p>		
	(7) मंडी जिला:		
	<p>जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी,</p> <p>थुनाग तहसील में पंचायतें:</p> <p>बागरा, चातरी, छोटधार, गारागुशैन, गाढ़ू, गरयास, जंझेली, जरयार, जोहार कल्हनी, कलवन, खोलानाल, लोथ, सिलिबगी, सोमाचन, थाचधार, ताची, थाना,</p> <p>धर्मपुर ब्लॉक की निम्नलिखित पंचायतें:</p> <p>बिंगा, कमलाह, सकलना, तान्यार और तारखोला,</p> <p>करसोग तहसील की पंचायतें - बालीधर, बगड़ा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुडी, मंज, पेखी, सैज, सरहन और तेबान,</p> <p>सुंदरनगर तहसील की पंचायतें -</p> <p>बोही, बटवारा, धनयारा, पौड़ा-कोठी, सेरी और शोजा</p>	2700	3400
	<p>(8) सिरमौर जिला:</p> <p>क) निम्नलिखित पंचायतें</p> <p>i) बानी, बखली (पच्छाड़ तहसील),</p> <p>ii) भरोग भनेरी (पांवता तहसील),</p> <p>iii) बिड़ला (नाहन तहसील),</p> <p>iv) डिब्बर (पच्छाड़ तहसील) और</p> <p>v) थाना कसोगा (नाहन तहसील)</p> <p>ख) थांगिरि पथ</p>	2700	3400
	(9) सोलन जिला: मांगल पंचायत	2700	3400
	(10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपर्युक्त (1) से (9) में शामिल नहीं हैं	1000	1200
13	उत्तराखंड: चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	4100	5300
14	पश्चिम बंगाल: दक्षिण 24 परगना जिला	1000	1200

सुंदरबन क्षेत्र (डैम्पियर हॉजेस की रेखा के दक्षिण), अर्थात्, भगतुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), झिंगा खली, सजनाखली, गोसाबा, अमलमथी (विद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नलगरहा, रायदिघी, भांची, पत्थर प्रतिमा, भागवतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सीकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुएमारी, कुलटोला, घुसीघाटा (कुल्टी)		
--	--	--

सुमित खंडेलवाल, महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./125/2025-26]

नोट: यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 1 जुलाई, 1979 को प्रकाशित हुआ था एवं तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किए गए थे :-

क्र.सं.	राजपत्र अधिसूचना संख्या	दिनांक
1.	एचओ/ईएसटी/2024-25/570	26.11.2024
2.	एचओ/ईएसटी/2021-22/297	20.11.2021
3.	एचओ/ईएसटी/2017-18/470	26.04.2017

विवरणात्मक ज्ञापन

ये विनियम जो पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए गए हैं, वे भारतीय बैंक संघ द्वारा सदस्य बैंकों की ओर से इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश और बैंकों के शीर्ष स्तरीय अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोटों की सहमत शर्तों के अनुसार हैं। इसलिए, ऐसे भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

UCO BANK

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2025

No.HO/EST/2025-26/25.—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the UCO Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services letter number 4/2/1/2022-IR, dated the 13th March, 2024, on and from the 1st November, 2022 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:—

1. (i) These regulations may be called the UCO Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2025.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,—

(i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely: —

'(f) "family" in relation to an officer for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession, means-

- (i) the spouse of the officer;
- (ii) wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children);
- (iii) wholly dependent physically or mentally challenged brothers or sisters with forty per cent. or more disability;
- (iv) widowed daughters and dependent divorced or separated daughters;
- (v) sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters; and
- (vi) parents wholly dependent on the officer:

Provided that in the case of physically or mentally challenged children, irrespective of age, they shall be construed as dependents even after their marriage subject to however fulfilling the income criteria for dependent.

Explanation 1.— The expression "wholly dependent family member" shall mean such member of the family having a monthly income not exceeding Rs.18,000/- and if the monthly income of one of the parents exceeds Rs.18,000/- or the aggregate of monthly income of both the parents exceeds Rs.18,000/-, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.

Explanation 2.— For the purposes of medical expenses reimbursement scheme and Leave Fare Concession, for all officers, that is, male or female, any two of the dependent father, mother, father-in-law, mother-in-law shall be covered. The officer shall have the choice to substitute either of the dependents, or both, once in a calendar year.

Explanation 3.— This definition shall be effective from the 1st day of April, 2024 and for the calendar year 2024, for the purpose of medical insurance scheme, the revised monthly income criteria of dependents shall be effective from the 1st day of November, 2024."

3. In regulation 4 of the said regulations, —

(a) the *Explanation* to sub-regulation (7) shall be omitted;

(b) for sub-regulations (8) and (9), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(8) On and from the 1st November, 2022, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.156500 – 4340/4 – 173860

Scale VI = Rs. 140500 - 4000/4 – 156500

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 - 135020

Scale IV = Rs.102300 – 2980/4 – 114220– 3360/2 – 120940

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.85920-2680/5– 99320 - 2980/2 - 105280

Scale II = Rs.64820–2340/1 - 67160 -2680/10 - 93960

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.48480-2000/7- 62480-2340/2-67160-2680/7-85920.

Explanation.— Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on the 31st October, 2022 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on the 1st November, 2022 on stage-to-stage basis, that is, on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual, except where provided otherwise.

(9) The scale of pay for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade shall be as under:

Top Executive Grade Scale VIII = Rs.253000 – 9000/4 – 289000.

(10) Nothing in sub-regulations (1) to (9) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(11) (a) On and from the 1st day of November, 2012, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III - 7.75 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V – 10 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI – VII - 11 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

(11) (b) On and from the 1st day of November, 2017, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III - 16.40 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 19 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VII - 20 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

(12) (a) On and from the 1st day of November, 2022, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I - 26.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale II – III - 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 30.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VII - 31.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

(12) (b) The Special Allowance for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade shall be as under:

Special Allowance Scale VIII = 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Note.— The special allowance referred to in sub-regulations 11(a), 11(b), 12(a) and 12(b) with applicable dearness allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including Defined Contributory Pension Scheme (N P S), Provident Fund and Gratuity.”.

4. In regulation 5 of the said regulations,—

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

(1) Subject to the provisions of sub-regulation (8) of regulation 4, on and from the 1st November, 2022, the increments shall be granted subject to the following, namely:—

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulations (8) and (9) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment (s) in the next higher Scale only as specified in clause (c) and clause (d) below, subject to their crossing the efficiency bar;
- (c) officers in Junior Management Grade Scale I, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher scale, shall be eligible for seven stagnation increments for every two completed years of service of which the first two shall be Rs. 2680/- each and the next five shall be of Rs. 2980/- each:
Provided that an officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of the fifth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of the fifth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (d) officers in Middle Management Grade Scale II, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher scale, shall be eligible for seven stagnation increments of Rs. 2980/- each for every two completed years of service:

Provided that an officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later: Provided further that an officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III, that is, those who are recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III shall be eligible for eight stagnation increments, each such increment for every two years for completed service after reaching the maximum of scale out of which first four stagnation increments shall be of Rs. 2980/- each and the next four stagnation increments shall be of Rs. 3360/- each:

Provided that an officer shall be eligible for the seventh stagnation increment two years after release of the sixth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the eighth stagnation increment four years after release of the sixth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (f) officers in Senior Management Grade Scale IV shall be eligible for five stagnation increments, each such increment for every two completed years of service after reaching the maximum of scale, of which first stagnation increment shall be of Rs. 3360/- each and the next four stagnation increments shall be of Rs. 3680/- each:

Provided that an officer shall be eligible for the third stagnation increment two years after release of the second stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the fourth stagnation increment four years after release of the second stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that an officer shall be eligible for the fifth stagnation increment six years after release of the second stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (g) officers in Senior Management Grade Scale V shall be eligible for four stagnation increments of Rs. 4000/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that an officer shall be eligible for the second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the third stagnation increment six years after reaching the maximum of scale or 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that an officer shall be eligible for the fourth stagnation increment eight years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (h) officers in Top Management Grade Scale VI shall be eligible for three stagnation increments for every two completed years of service after reaching the maximum scale of pay, out of which first two stagnation increments shall be of Rs. 4000/- each and the third stagnation increment shall be of Rs. 4340/-:

Provided that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment of Rs. 4000/- two years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment of Rs. 4000/- four years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment of Rs 4340/- six years after reaching the maximum of scale or 1st November, 2022, whichever is later;

- (i) officers in Top Management Grade Scale VII shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 4340/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment, two years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment, six years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later.

Note.— The increments as mentioned in clauses (c) to (i) of this sub-regulation shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation.— Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

(b) in sub-regulation (2),—

(i) before the *Explanation*, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that on and from the 1st November, 2022 officers completing Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) or Part II of CAIIB examination (CAIIB-II) shall be eligible for two increments in their scale of pay apart from one increment for completing Junior Associate of Institute of Indian Bankers’ (JAIIB) examination or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB-I):

Provided further that Officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022 and have already completed CAIIB or CAIIB- II shall be eligible for second additional increment from the 1st November, 2022 or date of passing CAIIB or CAIIB II, whichever is later:

Provided also that in case where an officer as on the 8th March, 2024, has already acquired or shall acquire hereinafter JAIIB (CAIIB-I) or CAIIB (CAIIB-II) after reaching the maximum of the scale of pay (in case of JAIIB or CAIIB), or after reaching the stage which is one stage less than the maximum of scale of pay [(in case of CAIIB or (CAIIB II)], and has not earned increments, otherwise entitled on account of acquiring such qualification, when there were no increments to provide in the scale of pay of those employees, the stagnation increment in such cases may be advanced by one year or two years, as the case may be.”.

(ii) in the *Explanation*, after clause (h) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:—

“(i) on and from the 1st November, 2022, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the following Table, namely:—

Table

(1)	(2)
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers (JAIIB) or Part I of the Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB-I)	Rs.1370/- per month one year after reaching maximum of the scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB-II)	(i) Rs1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale; (ii) Rs.3425/- per month two years after reaching maximum of the Scale; and (iii) Rs.5480/- per month three years after reaching maximum of the Scale:

Provided that an officer employee acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers(either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification, the first installment of

Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.”;

(iii) in the Note, after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely.—

“(vi) Officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022, and have already completed JAIIB (CAIIB-I) or CAIIB (CAIIB-II) and drawing Professional Qualification Pay -II shall be eligible for Professional Qualification Pay -III one year after the release of Professional Qualification Pay-II or from the 1st November, 2022, whichever is later.

(vii) Officers who have completed JAIIB (CAIIB-I) or CAIIB (CAIIB-II) and has reached the maximum in the scale of pay on or before the 1st November, 2022 and has not received the 1st stagnation increment on or before the 1st November, 2022, shall be eligible for Professional Qualification Pay-I on and from 1st November, 2022 and release of subsequent instalment of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of Professional Qualification Pay I under this clause.

(viii) Officers in Scale VIII shall not be eligible for Professional Qualification Pay and shall not form part of pay slip components.”;

(c) in sub-regulation (3),—

(i) the Note after clause (g) shall be omitted;

(ii) after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely: —

“(h) Other things being equal, the Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance, if any, for the post of Chief General manager in Top Executive Grade Scale-VIII shall be at the rates given in the Table below and shall remain frozen for the entire period of service:—

Table

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 1 st November, 2022 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
9000	669	9669.

(i) On and from the 1st November, 2022, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:—

Table

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 1 st November, 2022 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610

3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663.

Note.— (a) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Tables in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g) (h) and (i) of this sub-regulation shall be payable to those officers employees who are provided with bank's accommodation.

(b) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the aforesaid Table under clauses (h) and (i) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9) of regulation 4 is earned;

(c) Only officers who are in the service of the Bank on or before the 1st November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay, they are placed.

(d) On and from the 1st November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of professional qualification pay as in clause (c) of the *explanation* to sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released as on the 1st November, 2000.

(e) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(f) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of this sub-regulation, one year after reaching the maximum of the scale.”.

5. for regulation 7, the following regulation shall be substituted, namely:—

“7. Categorisation in appointed date.— Subject to the provisions of regulation 6, the various posts of officers in the Bank on the appointed date shall be categorised as specified in the Table below:—

Table

POSTS	GRADE or SCALE IN WHICH PLACED
(1)	(2)
Chief General Manager	Top Executive Grade Scale-VIII
General Manager	Top Executive Grade Scale-VII
Deputy General Manager	Top Executive Grade Scale-VI
Assistant General Manager	Senior Management Grade Scale-V
Chief Manager	Senior Management Grade Scale-IV
Senior Manager	Middle Management Grade Scale-III
Manager	Middle Management Grade Scale-II
Assistant Manager	Junior Management Grade Scale-I

Provided that any difficulty or anomaly arises out of the above categorisation, shall be referred to a committee consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer and such other person or persons as may be appointed by the Central Government for this purpose, for its decision.”.

6. In regulation 21 of the said regulations,—

(i) after sub-regulation (7) and before the *Explanation*, the following sub-regulation (8) shall be inserted, namely:—

“(8) On and from the 1st November, 2022,—

- (a) Dearness Allowance shall be payable at 1 per cent. of pay per percentage point of Index;
- (b) Dearness Allowance in the above manner shall be paid for every variation of rise or fall over 123.03 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index (CPI) for Industrial Workers Base 2016=100. 0.01% change in Dearness Allowance on pay for change in every second decimal place of CPI 2016 over 123.03 points;
- (c) The change in the Dearness Allowance rate shall be released on a quarterly basis on 1st May, 1st August, 1st November and 1st February based on the following, namely:—

D.A. release date	Quarterly average of CPI points of the months	Applicable for the month
1 st May	January, February and March	May, June and July
1 st August	April, May and June	August, September and October
1 st November	July, August and September	November, December and January
1 st February	October, November and December	February, March and April;

(d) there shall be no ceiling on Dearness Allowance;

(e) while working out quarterly average, only first two decimals shall be considered.”;

(ii) in the *Explanation*, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) to the *Explanation* in sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for Dearness Allowance.”.

7. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st November, 2022,—

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.35 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following Table, namely:—

Table

Place of work	House Rent Allowance
(1)	(2)
(i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	10.0% of Pay

Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	9.0% of Pay
(iii) Other places	8.0% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.35 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above Table.

Note.— The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall be also be restricted to 150 per cent. of House Rent Allowance as hitherto.”.

8. In regulation 23 of the said regulations,—

(a) for sub-regulations (1) and (2), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st November, 2022, if an officer is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place shall be payable.

Table

Places	Rate
(1)	(2)
(i) Places in Area 1 and above and in the State of Goa	Rs. 2300/- per month
(ii) Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Rs. 1900/- per month.

(2) On and from the 1st November, 2022, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations:

Provided that where at any of the places indicated in column (1) of the Schedule, Hill and Fuel Allowance as provided under sub-regulation (10) is also payable, then the officer shall be eligible to draw only higher of the two allowances and not both.”;

(b) for sub regulations (4), (5), (6) and (7) the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

“(4) On and from the 1st April, 2024, if an officer is transferred from one place to another in the middle of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.2500/- per month per child with a maximum upto two children, from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year:

Provided that such allowance shall cease to be payable if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st April, 2024, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs. 7500/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where such officer is deputed to an organisation which is located at the same place or to the training establishment not owned by the Bank, where he was posted immediately prior to his deputation or to the training establishment not owned by the Bank, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs. 3750/- per month:

Provided further that where an officer is deputed to another office or branch within the same municipal limits or urban agglomeration, in Metro or Major A class cities where the distance of such deputation is 20 kilometers and more from the parent branch or office, he shall be eligible for halting allowance as mentioned in sub-regulation (4) of regulation 41.

(6) On and from 1st April, 2024, if an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than four days at a time or an aggregate of four days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 15 per cent. of his Basic Pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that, where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating allowance for a period of one year from the date on which review of the categorisation takes effect.

(7) On and from the 1st April, 2024, an officer shall be entitled for a closing allowance of Rs.1500/- per quarter for each of the closing.”;

(c) for sub-regulations (10), (11), (12) and (13) the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

“(10) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for the Hill and Fuel Allowance as specified in the table below, namely:—

Table

Place	Rate
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.1450/- per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.1900/- per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month.

Note.—

- (a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000

metres or more, will be paid Hill and Fuel Allowance at the same rate as is payable at centres with an altitude of 1000 metres and above.

- (b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn. Except in respect of an officer who was posted in such a centre prior to 1st May, 1989 and remains posted at that centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as at 30th April, 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay.

(11) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for Learning Allowance of Rs 850/- per month along with Dearness Allowance thereon.

Note.— The Learning Allowance with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, that is, Pension including Defined Contributory Pension Scheme, New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.

(12) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for a Fixed Location Allowance of Rs.1200/- per month, who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance, which shall not be reckoned for payment of Dearness Allowance, superannuation benefits, that is, pension including Defined Contributory Pension Scheme, New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.

(13) (a) From the financial year 2023-24, Performance Linked Incentive shall be payable to all officer employees based on the metrics put in place by the Competent Authority of the Bank as per their priorities from the following select parameters:

(i) Current Account Savings Account (ii) Non-Performing Asset (iii) Special Mention Account (iv) Non – Interest Income (v) Total Business (vi) Profitability (vii) Return On Asset or Return On Equity (viii) Government Schemes.

(13)(b) The Performance Linked Incentive amount shall be payable in 0-15 (maximum) number of days of pay (Basic + Dearness Allowance) depending on the metrics put in place by the Competent Authority as mentioned in clause (a).”.

9. In regulation 24 of the said regulations,—

(a) for sub-regulation (1) the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of own certificate of the officer of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:—

Table

Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	(2)
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.13000/- per annum or the amount incurred, whichever is less.
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.15400/- per annum or the amount incurred, whichever is less.

Note 1.— An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Note 2.— For the calendar year 2022, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2022 and December, 2022.”.

(b) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(4) All officer employees shall also be eligible for reimbursement of Rs 500/- per year towards eye check-up.”.

10. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st November, 2022, a sum equal to 0.35 per cent. of the Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.075 per cent. of Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

11. In regulation 31 of the said regulations, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that where the sanctioning authority refuses or postpones the leave of the officer, the sanctioning authority shall record the reasons for the same in writing.”.

12. In regulation 32 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(3) On and from the 1st April, 2024, an officer employee shall be eligible to avail two days casual leave for half-a day on four occasions in a year, out of which two occasions shall be in the morning and two occasions in the afternoon:

Provided that casual leave under this category shall be availed after applying twenty-four hours in advance:

Provided further that at the time of carrying over the balance in casual leave to unavailed casual leave account, the fraction in the balance, if any, shall be ignored.”.

13. In regulation 33 of the said regulations,—

- (a) for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

“(4) On and from the 1st June, 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred and seventy days except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that on and from the 1st April, 2024, encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of two hundred and fifty-five days:

Provided further that an officer shall also be eligible for encashment of privilege leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an officer who have already completed fifty-five years of age and above shall be eligible to encash privilege leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement.

- (5) An officer desiring to avail privilege leave shall ordinarily give not less than ten days notice of his intention to avail such leave except for the purpose of Leave Fare concession:

Provided that on and from the 1st April, 2024, no such advance notice of ten days shall be required for availing privilege leave for office bearers and Executive Committee members of a registered Trade Union.”;

- (b) after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(7) On and from the 1st April, 2024, for the purposes of calculating privilege leave, all types of leave availed except casual leave and mandatory leave shall be excluded.”.

14. In regulation 34 of the said regulations,—

- (a) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that on and from the 1st April, 2024, an officer shall be eligible for sick leave at the rate of one month for each year of service:

Provided further that the total number of sick leave (including additional sick leave mentioned in regulation 35) shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer.”;

- (b) after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(6) On and from the 1st April, 2024, a single male parent employee may avail sick leave for the sickness of his children of eight years and below subject to production of medical certificate.

(7) On and from the 1st April, 2024, a women employee may avail one day sick leave per month without production of medical certificate.

(8) On and from the 1st April, 2024, officer employees may avail sick leave for the sickness of their special child of fifteen years and below for a maximum period of ten days in a calendar year subject to production of medical certificate.

(9) On and from the 1st April, 2024, officer employees of the age of fifty-eight years and above, may avail sick leave towards hospitalisation of his or her spouse at a centre other than place of work for a maximum period of thirty days in a calendar year.”.

15. In regulation 36 of the said regulations,—

(a) for sub-regulation (1) (a), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1)(a) A female officer employee shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months:

Provided further that on and from the 1st April, 2024, in case of delivery of more than two children in one delivery, the period of maternity leave shall be twelve months:

Provided also that maternity leave may be availed combining with any other kind of leave except casual leave.”;

(b) for sub-regulation (1) (d), the following sub-regulation shall be substituted, namely: —

“(1) (d) A female officer employee may avail leave once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (a) leave will be granted for adoption of only one child;
- (b) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;
- (c) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;
- (d) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.”;

(c) after sub regulation 1(e), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(1) (f) On and from the 1st April, 2024, maternity leave may be availed for in vitro fertility (IVF) treatment subject to production of medical certificate within the overall limit of twelve months.

(1) (g) On and from the 1st April, 2024, special maternity leave may be availed by a female employee upto sixty days in case of a still born or death of the infant within twenty-eight days of birth.”.

16. for regulation 37A of the said regulation, the following regulation shall be substituted, namely:—

“37A.Special casual leave and special leaves.— (1)With effect from the 1st November, 2020, an officer employee shall be eligible for special casual leave on occasions when the branch where the officer is working or the place where he is residing, is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, etc,

(2) With effect from the 1st November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days special casual leave.

(3) With effect from the 1st April, 2024, the principal officer bearers of All India Officers' Unions or Associations shall be granted Special Leave upto twenty-five days in a calendar year.

(4) With effect from the 1st April, 2024, officers who are defense representatives in departmental enquiry may avail one day special leave for the purpose of preparing the defense submission of an officer employee:

Provided that such special leave shall be availed for a maximum of ten occasions in a year.

(5) An officer may also be granted special casual Leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.”.

17. After regulation 37A of said regulations, the following regulation shall be inserted, namely:—

“37B. Bereavement Leave.— An officer employee shall be granted bereavement leave on the demise of the family members (Spouse, children, parents and parents-in-law) for such number of days as may be decided by the Board from time to time:

Provided that the intervening holidays will form part of the bereavement leave:

Provided further that the said leave should be availed within a maximum period of fifteen days of the demise:

Provided also that the said leave shall not be considered as ‘Active service’ for the purpose of calculation of privilege leave.”.

18. In regulation 41 of the said regulations,—

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: —

“(1) On and from the 1st April, 2024, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:—

(a) an officer in Junior Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st class by any train including Premium Trains like Rajdhani or Shatabdi or Tejas or Vande Bharat or Amrit Bharat, etc. (except luxury trains):

Provided that such officer may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(b) an officer in Middle Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st Class by any train including Premium Trains as mentioned in clause (a):

Provided that he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than five hundred kilometers;

Provided further that he may travel by air (economy class) even for shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

- (c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by any train including premium trains (as mentioned in clause (a)) or by air (economy class);
- (d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed five hundred kilometers:
Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail, only the rest of the distance should normally be covered by car;
- (e) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle;
- (f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail;
- (g) an officer shall be eligible for fare by premium trains (except luxury trains).

Note 1.— Goods and Service Tax Charges levied on train fare shall be over and above the entitlement.

Note 2.— In view of prevailing dynamic fare system, the cost of train tickets charged on the date of booking shall be reimbursed.”;

(b) in sub-regulation (4), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

“4 (a) On and from the 1st April, 2024, an officer in the grades or scales set out in column (1) of the Table shall be entitled to *per diem* Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:—

Table

Grades or Scales of officers (1)	Halting Allowance (2)			
	Metro Rs.	Major 'A' Class cities Rs.	Area I Rs.	Other Places Rs.
Officers in Scale VI and above	4050	2925	2475	2150
Officers in Scale IV and V	3375	2925	2475	2150
Officers in Scale I, II and III	2925	2475	2150	1800:

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.— For the purpose of computing Halting allowance *per diem* shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.

4(b) An officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the table below may be reimbursed the actual hotel expenses restricting to single room accommodation charges in India Tourism Development Corporation hotels of the corresponding star category set out in column (2) of the Table below:

TABLE

Grades or Scales of officers	Eligibility to stay
(1)	(2)
Scale-VI, VII and VIII	4 * Hotel
Scale-IV and V	3 * Hotel
Scale-II and III	2 * Hotel (Non AC)
Scale-I	1 * Hotel (Non AC)

The Board may specify the additional limit to be reimbursed in excess of the limits specified above, in accordance with the guidelines of the Central Government.’.

19. In regulation 42 of the said regulations,—

(a) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(3) On and from the 1st April, 2024, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

Table

Grade or Scale	Amount
(1)	(2)
Senior Management and Top Executive (Officers in Scale IV and above)	Rs.50000/-
Junior Management and Middle Management (Officers upto Scale III)	Rs.40000/-.”.

(b) in the sub-regulation (4), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that on and from the 1st April, 2024, where no residential accommodation is made available by the Bank to an officer at the new place of posting and where such an officer may incur additional expenses in the process of taking over charge, for reasons beyond his control, the Competent Authority, from the date of joining of such officer at the new place, may on merits consider grant of either lodging and Boarding charges or Halting Allowance for a period of fifteen days or till the time the quarters are made available to him, whichever is earlier.”.

20. for regulation 44 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“44 (1) During each block of four years, an officer shall be eligible for Leave Travel concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route.

(2) With effect from the 1st April, 2024, alternatively, an officer by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession

(other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 5,500 kilometers (one-way) for officers in Junior Management Grade Scale I, Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III and 6,500 kilometers (one-way) for officers in Senior Management Grade Scale IV and above:

Provided that an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from the 1st April, 2024, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession, shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement shall be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled whichever is less and the same rules shall apply when an Officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III avails Leave Travel Concession where the distance is less than five hundred kilometres.

(4) Once in every four years, when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his privilege leave not exceeding thirty days at a time or he may, while travelling in one block of two years to his home town and in other block any place in India, be permitted encashment of privilege leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the leave travel concession is availed shall be admissible:

Provided that an officer, at his option shall be permitted to encash one day additional privilege leave for donation to Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the bank to remit the amount to the fund.

(5) Leave Travel concession can be availed independently where both husband and wife are working in the same Bank.

(6) For employees working in North-east States, Leave Travel Concession shall begin from Guwahati and the eligible train fare from their place of work to Guwahati shall be additionally paid.

(7) The eligible fare for Andaman and Nicobar Islands to Chennai or Kolkata, Lakshadweep to Kochi, far-flung area branches in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jammu and Kashmir or any other areas which are not directly connected by train shall be additionally reimbursed under Leave Travel Concession in addition to normal entitlement for the employees working in these areas to the nearest major Railway Station.

(8) Leave Travel concession facility shall be allowed for an escort who accompanies an officer with benchmark disabilities on the journey subject to following conditions, namely:—
 (a) prior approval of the competent authority is obtained on each occasion;
 (b) the nature of physical disability of the officer is such as to necessitate an escort for the journey and in case of doubt, the decision of the head of the Department or Controller shall be final;

- (c) the officer with such benchmark disabilities does not have an adult family member as dependent to accompany him or her;
- (d) the officer with such benchmark disabilities and the escort shall avail of the concession, if any, in the Rail or Bus fare as might be extended by Railways or State Roadways authorities in such cases; and
- (e) any other person who is entitled to Leave Travel concession as dependent does not accompany the officer with such benchmark disabilities on the journey.
- (9) Where an officer has applied for Leave Travel concession or leave in advance and has also booked the tickets and the Leave Travel concession is declined or deferred by the management, the cancellation charges shall be reimbursed by the Bank;
- (10) Where an officer has applied for Leave Travel concession or leave as per stipulated time and the same is sanctioned and when advance booking of train tickets is not possible, tickets purchased under Tatkal or Premium Tatkal shall be reimbursed.”.

21. for the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE

[See sub-regulation (2) of regulation 23]

On and from the 1st day of November, 2022, an officer shall be eligible for Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified, either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:—

Table

Special Area Allowance			
Sl. No.	Place	Allowances (in Rs.)	
		Pay below Rs.48,481/-	Pay above Rs. 48,481/-
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mizoram		
	(a) Chimgtuipui District and areas beyond 25 kms from Lunglei Town in Lunglei District;	4100	5300
	(b) Entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kms from Lunglei town;	4100	5300
	(c) Entire Aizawl District.	2700	3400
2.	Nagaland	4100	5300
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands;	4100	5300
	(b) South Andaman(including Port Blair)	4100	5300
4.	Sikkim	4100	5300
5.	Lakshadweep Islands	4100	5300

6.	Assam	1000	1200
7.	Meghalaya	1000	1200
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	4100	5300
	(b) Throughout Tripura except Difficult areas	2700	3400
9.	Manipur	2700	3400
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh;	4100	5300
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except Difficult areas	2700	3400
11A.	Union territory of Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	4100	5300
	(2) Udhampur District:		
	(a) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, Thakrakote and Nagote;	4100	5300
	(b) All Areas in Mahore tehsil other than those included in (c) below;	4100	5300
	(c) Areas upto Goel from Kamban Side and Areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre	4100	5300
	(3) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kashmir Tehsil.	4100	5300
	(4) Baramulla District:		
	(a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua	4100	5300
	(b) Matchill	4100	5300
	(5) Poonch and Rajouri District: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	2700	3400
	(6) Areas not included in (1) to (5) above, but which are within the distance of 8 kms. from the Line of Actual Control (LOC) or at places which may be declared as qualifying for Border Allowance from time to time by the State Government for their own staff.	2700	3400
B.	Union territory of Ladakh: Leh District: Noyama and Nobre Zaskar All other places in the District	4100	5300
12.	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba District		
	(a) Pangi Tehsil, Following Panchayats and Villages in Bharmour Tehsil: Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tunda	4100	5300

	Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata;		
	(b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in (a) above;	4100	5300
	(c) Jhandru Panchayat in Bhartiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet Proper).	2700	3400
	(2) Kinnaur District		
	(a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno or Charang Panchayats; 15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi; Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat areas specified above;	4100	5300
	(b) Entire district other than areas included in (a) above;	4100	5300
	(3) Kullu District		
	(a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga;	4100	5300
	(b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burao of Tehsil Nirmand).	2700	3400
	(4) Lahaul and Spiti District: Entire area of Lahaul and Spiti.	4100	5300
	(5) Shimla District		
	(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chandi-Branda;	4100	5300
	(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish; Ghor Chaibis of Pargana Sarahan;	4100	5300
	(c) (I) Chopal Tehsil (i)Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, (ii) Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, (iii) Pargana Barabis; and (iv) Kasba Rampur and Ghor Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil; (II) Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu)	2700	3400
	(6) Kangra District:		
	(a) Areas of Bara Bhawal and Chhota Bhawal;	4100	5300
	(II) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town;	2700	3400

	<p>(a) Women's ITI, Dari;</p> <p>(b) Mechanical Workshop, Ramnagar;</p> <p>(c) Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh;</p> <p>(d) CRSF Office at lower Sakoh;</p> <p>(e) Kangra Milk Supply Scheme, Dugiari;</p> <p>(f) HRTC Workshop, Sadher;</p> <p>(g) Zonal Malaria Office, Dari;</p> <p>(h) Forest Corporation Office, Shamnagar;</p> <p>(i) Tea Factory, Dari;</p> <p>(j) I.P.H. Sub- Division, Dari;</p> <p>(k) Settlement Office, Shamnagar;</p> <p>(l) Binwa Project, Shamnagar.</p> <p>(II) Palampur Town, including HPKV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town:</p> <p>(a) H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus;</p> <p>(b) Cattle Development Office or Jersey Farm, Banuri;</p> <p>(c) Sericulture Office or Indo- German Agriculture Workshop or HPPWD Division, Bundla;</p> <p>(d) Electrical Sub-Division, Lohna;</p> <p>(e) D.P.O. Corporation, Bundla;</p> <p>(f) Electrical HPSE Division, Ghuggar</p>		
	(7) Mandi District:		
	<p>Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil,</p> <p>Panchayats in Thunag Tehsil:</p> <p>Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjheli, Jaryar, Johar Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana,</p> <p>Following Panchayats of Dharampur Block:</p> <p>Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah,</p> <p>Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban,</p> <p>Panchayats of Sundernagar Tehsil –</p> <p>Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja</p>	2700	3400
	<p>(8) Sirmaur District:</p> <p>(a) Following Panchayats of</p> <p>(i) Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil);</p> <p>(ii) Bharg Bheneri (Paonta Tehsil);</p> <p>(iii) Birla (Nahan Tehsil);</p> <p>(iv) Dibber (Pachhad Tehsil); and</p> <p>(v) Thana Kasoga (Nahan Tehsil);</p> <p>(b) Thansgiri Tract</p>	2700	3400

	(9) Solan District: Mangal Panchayat.	2700	3400
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.	1000	1200
13	Uttarakhand: Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	4100	5300
14	West Bengal: South 24 Parganas District Sunderban Areas (south of Dampier Hodge's line), namely, Bhagatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhinga Khali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, Pathar Pratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, Kuemari, Kultola, Ghushighata (Kulti)	1000	1200.”.

SUMIT KHANDELWAL, GENERAL MANAGER

[ADVT.-III/4/Exty./125/2025-26]

Note: UCO bank (Officers') Service Regulations, 1979 were published on the 1st day of July, 1979 and subsequently amended vide the following notifications:—

Sl No.	Gazette Notification No	Date
1.	HO/EST/2024-25/570	26.11.2024
2.	HO/EST/2021-22/297	20.11.2021
3.	HO/EST/2017-18/470	26.04.2017

EXPLANATORY MEMORANDUM

These Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Note signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.